CMYK

डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 16 जुलाई, 2025, डिस्पैच दिनांक 16 जुलाई, 2025

| वर्ष 69 | अंक 04 | भोपाल | 16 जुलाई, 2025 | पृष्ठ 24 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सहकारिता युवाओं का भविष्य, समाज की समरसता का आधार : मुख्यमंत्री

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर 'सहकारी युवा संवाद' का ऐतिहासिक आयोजन, युवाओं को आत्मनिर्भरता व नवाचार का मंत्र

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता को मिल रहे नए आयाम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

नए कार्यों में सहकारी समितियों को दी जा रही है प्राथमिकता

युवाओं को स्वावलंबी बनाने का सशक्त माध्यम हैं सहकारी समितियां

युवाओं को दिए सहकारिता के मूल मंत्र

किसी भी काम में सफल होने के लिए जरूरी है मजबूत आत्मविश्वास

सफलता के लिए कार्य अनुभव और उसके संबंध में जानकारी आवश्यक

सहकारिता को लेकर लागू है पारदर्शी व्यवस्था, अब 30 दिन में हो रहा नई समिति का पंजीयन

महिलाएं समिति बनाकर सतपुड़ा टाइगर रिर्जव में चला रही हैं सफारी

मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर युवाओं से किया संवाद

विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का किया समाधान

भोपाल : भोपाल स्थित समन्वय भवन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित एवं अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर 'सहकारी युवा संवाद' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर परमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवने प्रदेश के युवाओं को सहकारिता के नवाचार, संभावनाओं और भविष्य की दिशा से अवगत कराया।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के सहकारिता क्षेत्र को नए आयाम मिल रहे हैं। दुग्ध-उत्पादन, औद्योगिक विकास सहित अन्य क्षेत्रों में हो रहे नए कार्यों में सहकारी समितियों को प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता समाज को एक करने के साथ ही युवाओं को बेरोजगारी से बचाने का माध्यम है। रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। युवाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है और वर्ष 2025 को रोजगार एवं उद्योग वर्ष के रूप में मना रही है। उन्होंने तीन नए आपराधिक कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटी है, क्योंकि आंख पर पट्टी रहते हुए न्याय कैसे हो सकता है। नागरिकों के मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित हैं और इसी भावना से व्यक्तियों के आपसी स्वावलंबन और सहभागिता का समावेश सहकारिता में है। वर्तमान सरकार में सहकारिता को लेकर व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है। नई समिति की पंजीयन प्रक्रिया 30 दिन में पूर्ण की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस के अवसर पर समन्वय भवन में म.प्र. राज्य सहकारी संघ एवं अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से आयोजित सहकारी युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सहकारिता ध्वज फहराकर समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों को पौधा भेंटकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सहकारी युवा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालयीन विद्यार्थियों से संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सहकारिता से उद्योग प्राप्त करने वाली 30 महिलाओं को सिलाई मशीन टूल किट वितरण के प्रतीक स्वरूप एक महिला को सिलाई किट प्रदान की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में सहकारिता का आंदोलन खड़ा करने के लिए गुजरात में अमूल की स्थापना की। हजारों लोगों को दुग्ध-उत्पादन से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने और बेरोजगारी खत्म करने का कार्य किया। राज्य सरकार भी दुग्ध-उत्पादन बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। अभी दुग्ध-उत्पादन में प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जो भविष्य में शीर्ष पर पहुंचेगा। इसी उद्देश्य से दुग्ध-उत्पादन में प्रदेश का योगदान 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सहकारिता क्षेत्र की बड़ी भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं को दिए मूल मंत्र

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं से संवाद करते हुए उन्हें सहकारिता क्षेत्र से जुड़े मूल मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता में आने का एक सूत्र है- जब भी कोई नया काम करें तो आत्मविश्वास मजबूत रखें। युवा जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, पहले उसका अनुभव लें और यह भी देखें कि सहकारी समिति के माध्यम से इस क्षेत्र में क्या-क्या किया जा सकता है। सहकारी समिति के नेतृत्वकर्ता का दायित्व है कि पहले वह स्वयं पूरी जानकारी रखें और दूसरे साथियों को भी बताएं।

सभी क्षेत्रों में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवाओं के जीवन की असली परीक्षा कॉलेज की शिक्षा पूर्ण होने के बाद शुरू होती है। राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश वन्य संपदा और जलराशियों से संपन्न है। प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार संकल्पित है। हमारे युवा सभी साधनों से संपन्न होकर प्रदेश को आग बढ़ाए, इसी भावना से राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से अलग-अलग मंचों पर युवाओं से संवाद किए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में उन्हें भी नेतृत्व का अवसर मिले। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा। सहकारिता और भारतीय दर्शन के माध्यम से हम सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं।

आय बढ़ाने के साथ समाज को एक करने की पहल है सहकारिता

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है। उन्होंने विकसित भारत के लिए सहकारिता को आगे बढ़ाने पर बल दिया। देश में सहकारिता मंत्रालय बनाकर केन्द्रीय मंत्री

(शेष अगले पृष्ठ पर)

CMYK

(पिछले पृष्ठ का शेष)

सहकारिता युवाओं का भविष्य, समाज की ....

श्री अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी। देश का इतिहास है कि जहां व्यक्ति है, वहां सहकारिता है। जब व्यक्ति का एक-दूसरे से समन्वय होगा, तभी देश एक होगा। सहकारिता केवल आय बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि देश और समाज को एक करने की पहल है। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में सहकारिता को आत्मसात करना होगा। हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों की जिज्ञासा का किया समाधान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के सामने महाविद्यालय छात्र-छात्राओं ने युवा संवाद कार्यक्रम में कई जिज्ञासाएं रखीं। एक छात्रा के सहकारी समिति बनाने की प्रक्रिया और शासकीय कार्य-प्रणाली संबंधी प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में सहकारिता में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की गई है और नई समितियों का पंजीयन 30 दिन में पूर्ण हो रहा है। एक अन्य छात्रा ने सहकारिता संबंधी विषय स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव रखा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हर विषय पाठ्यक्रम में रखना कठिन है। लोगों को स्वयं सहकारिता की ओर पहल करनी चाहिए। सहकारिता में सबका स्वागत है, इसमें शिक्षा या आय का कोई बंधन नहीं है।

मढ़ई क्षेत्र में जिप्सी चलाने वाली संगीता का मंच से कराया परिचय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में कई नवाचार हो रहे हैं। इसी के अंतर्गत को-ऑपरेटिव पब्लिक पार्टनरशिप (सीपीपीपी) के माध्यम से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी चलाने के कार्य में भी महिलाओं की समिति सक्रिय है। उन्होंने मढ़ई क्षेत्र में जिप्सी चलाने वाली संगीता सोलंकी का मंच से परिचय कराया। संगीता ने बताया कि बाघ सहित कई वन्य प्राणियों से समृद्ध मढ़ई क्षेत्र में वे बिना डर के पर्यटकों को जंगल सफारी कराती हैं और प्रति माह लगभग 14 हजार रूपए की आय हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजा हरिशचंद्र और प्रेमचंद की कहानी पंच-परमेश्वर का उदाहरण देते हुए सहकारी समितियों के संचालन में पारदर्शिता, स्पष्टता और न्यायप्रियता की महत्ता का उल्लेख किया।

विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस कार्यक्रम में मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे:

- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग
- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग श्री अशोक वर्णवाल
- आयुक्त, सहकारिता श्री मनोज कुमार पुष्प
- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ श्री ऋतुराज रंजन

श्री अशोक वर्णवाल ने स्वागत भाषण में सहकारिता की पारदर्शी नीतियों और युवाओं की सहभागिता पर प्रकाश डाला, वहीं श्री मनोज पुष्प ने आभार प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। "सहकारी युवा संवाद" न केवल युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी दिया कि सहकारिता महज़ एक आर्थिक तंत्र नहीं, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समरसता और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। इस आयोजन की सफलता में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज, और सहकारिता विभाग की भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय रही।

मछुआरों की सुरक्षा और समृद्धि सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

निगरानी के लिये हाईटेक ड्रोन और जीपीएस प्रणाली

ट्रांजिट हाउस, फ़्लोटिंग प्लेटफ़ॉर्म और अत्याधुनिक केवट प्रशिक्षण संस्थान बनेगा

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मछुआरों की सुरक्षा और समृद्धि सरकार की प्राथमिकता है। उनकी सुरक्षा की दिशा में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कंट्रोल कमांड सेंटर और ट्रांजिट हाउस जैसी पहल की जा रही हैं। राज्य के बड़े जलाशयों में मछुआरों की सुरक्षा और मत्स्य बीज संचयन की निगरानी के लिये आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के सबसे बड़े जलाशयों में शामिल इंदिरा सागर में ड्रोन, जीपीएस और सीसीटीवी युक्त आधुनिक कमांड कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। आपात स्थिति में इस प्रणाली से मछुआरों को शीघ्र सहायता पहुंचाई जा सकेगी। ये पहल ब्रीडिंग ग्राउंड के चिन्हांकन के साथ मत्स्य आखेट पर निगरानी को और ज़्यादा आसान, सुलभ और प्रभावशाली बनाएगी। कमांड कंट्रोल रूम की मदद से मुख्यालय स्तर से ही 24X7 निगरानी संभव हो सकेगी। ड्रोन के माध्यम से जल क्षेत्र की लाइव मॉनिटरिंग और जीपीएस सिस्टम से नावों की ट्रैकिंग की जा सकेगी और आपात स्थिति में मछुआरों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

मछुआरों के लिए बनेंगे ट्रांजिट हाउस और फ़्लोटिंग प्लेटफ़ॉर्म

मत्स्य महासंघ के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों को कई बार 15 दिन से लेकर एक महीने तक खुले टापुओं या जलाशय के किनारों पर अपनी नावों में रात्रि विश्राम करना पड़ता है। वर्षा ऋतु में टापुओं का जलस्तर बढ़ जाता है, ऐसे में मछुआरों को जलीय जीव-जंतुओं से जान-माल की हानि की आशंका बनी रहती है। मछुआरों को इससे बचाने के लिए महासंघ ने गांधी सागर और इंदिरा सागर के टापुओं पर 5 ट्रांजिट हाउस और जल के मध्य 2 फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। मछुआरों के लिए इसमें आपातकालीन स्थिति में भोजन निर्माण, सोलर मोबाइल चार्जिंग और बायो टॉयलेट जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

राज्य सरकार की यह पहल मछुआरों की सुरक्षा और सुविधा को बेहतर बनाएगी, साथ ही जल आधारित संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन और मत्स्य उत्पादन की वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आधुनिक तकनीक के समावेश से अब राज्य में मत्स्याखेट और मछलीपालन नए आयाम स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हैं।

भोपाल में बनेगा आधुनिक केवट प्रशिक्षण संस्थान

राज्य में मॉडर्न एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अहम पहल की जा रही है। केन्द्र सरकार की फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट फंड योजना के तहत भोपाल में 5 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक केवट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। इस संस्थान में केज कल्चर, बायोफ्लॉक, रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम, मछलियों की हाइजेनिक हैंडलिंग, फिश प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वैल्यूएडिशन जैसे विषयों पर मछुआ समुदाय को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मछुआरों को इससे वैश्विक मानकों के अनुरूप मछली पालन तकनीक की जानकारी और व्यावसायिक दक्षता प्राप्त होगी।

PACS को सशक्त बनाने नई तकनीकों का समावेश - सचिव डॉ. भूटानी

नई दिल्ली में कार्यशाला में बोले: 80,000 पैक्स होंगे कम्प्यूटरीकृत, सहकारी बैंकिंग होगी पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने नई दिल्ली में पीएचडी हाउस में आयोजित PACS में उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय का गठन एक ऐतिहासिक कदम था

अल्पावधि ऋण सुविधाओं के माध्यम से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 42% हो गई है, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि PACS ग्रामीण भारत के लिए लाभकारी रहे हैं

सहकारी बैंकिंग ढांचे को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए, अपने परिचालन में पारदर्शिता लानी चाहिए तथा अपने मानव संसाधन संबंधी मुद्दों का समाधान करना चाहिए ताकि वे प्रतिस्पर्धी बन सकें

अब लक्ष्य 80,000 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करना तथा भारत सरकार की सभी योजनाओं को पैक्स के साथ एकीकृत करके उन्हें जीवंत आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तित करना है

मंत्रालय PACS को समावेशी, जीवंत और निर्बाध, कुशलतापूर्वक और पारदर्शिता के साथ कार्य करने योग्य बनाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करेगा और उन्हें प्रणालियों में एकीकृत करेगा

नई दिल्ली | सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने नई दिल्ली में पीएचडी हाउस में आयोजित PACS में उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) के CEO श्री रंजीत मेहता और सहकारिता मंत्रालय तथा भाग लेने वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, NABARD, NCDC, NFDB, NCCT, IFFCO, KRIBHCO आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे। दिन भर चले इस कार्यशाला में 12 राज्यों के पैक्स के 122 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के ढांचे में डिजिटल इंडिया के युग में पैक्स, सटीक कृषि उपकरणों का लाभ उठाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट टेक्नॉलाजी, सहकारी फिनटेक (FinTech) और नीतिगत नवाचार तथा तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और मिज़ोरम में सफलता की कहानियों पर चर्चा शामिल थी।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया जो भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। सहकारी संस्थाएँ 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं, इस तरह की पहली ऋण संस्था 1904 में चेन्नई के पास स्थापित की गई थी। आज 1 लाख से अधिक पैक्स हैं जिनके 13 करोड़ से अधिक सदस्य हैं।

डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि आज भी PACS की अल्पावधि ऋण सुविधाओं के माध्यम से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 42% हो गई है, हालांकि समग्र अल्पावधि ऋण में सहकारी ऋण संस्थानों की हिस्सेदारी में कुल मिलाकर 15% की कमी आई है। पर इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि PACS जैसी संस्थाएँ ग्रामीण भारत के छोटे और सीमांत किसानों की सेवा करके स्पष्ट रूप से लाभकारी रही हैं।

डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि देश में करीब 2000 बैंकिंग लाइसेंस में से 1900 लाइसेंस सहकारी क्षेत्र में हैं, 100 लाइसेंस अन्य बैंकों के पास हैं। सबसे छोटी ऋण संरचनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और ये नई तकनीक को अपनाने में अक्षम रहीं हैं, जिसके कारण सीमित बैंकिंग उत्पादों के साथ सहकारी बैंकों के कामकाज पर कुछ स्तर तक प्रतिबंध हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के गठन के बाद, सहकारी क्षेत्र के बैंकिंग मुद्दों को आरबीआई, वित्त मंत्रालय और आयकर विभागों के साथ उठाया गया है, और अब समय आ गया है कि सहकारी बैंकिंग संरचना नई तकनीकों को अपनाए, अपने संचालन में पारदर्शिता लाए और अपने मानव संसाधन मुद्दों को हल करके खुद को प्रतिस्पर्धी बनाए।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने कहा कि पहले PACS केवल ऋण या कृषि के लिए सामग्री प्रदान करने के लिए थे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने PACS को मजबूत करने और समाज के लिए उनकी भूमिका बढ़ाकर उन्हें व्यवहार्य बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने PACS को सक्षम करने के लिए संघीय मॉडल के अनुरूप मॉडल उप-नियम बनाए हैं ताकि वे 26 विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में खुद को विविधता प्रदान करके आगे की आकांक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ जीवित रह सकें। सहकारिता मंत्रालय ने 4 साल की छोटी सी अवधि में सहकारिता के विभिन्न आयामों से जुड़ी 60 से अधिक पहल शुरू की हैं।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाया गया दूसरा बड़ा कदम, सहकारिता के राष्ट्रीय डाटाबेस का निर्माण था, जो केंद्र और राज्यों दोनों के लिए सहकारी संस्थाओं में मौजूदा गैप की पहचान करने और सहकारिता के सिद्धांतों पर राष्ट्र के विकास के लिए क्षेत्रों में मौजूद vacuum को भरने के लिए योजना बनाने में सक्षम बनाता है।

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मंत्रालय द्वारा सहकारी ऋण संस्थाओं (PACS) के बुनियादी ढांचे का कम्प्यूटरीकरण किया जाना तीसरा बड़ा कदम था। PACS कम्प्यूटरीकरण योजना में अब तक लगभग 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और अब लक्ष्य 80,000 PACS का कम्प्यूटरीकरण करना और भारत सरकार की सभी योजनाओं को PACS के साथ एकीकृत करके उन्हें जीवंत आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं में बदलना है।

डॉ. भूटानी ने PACS डिजिटलीकरण के लाभों की तुलना रेलवे टिकट कम्प्यूटरीकरण से की और कहा कि डिजिटलीकरण से पीएसीएस की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता आएगी तथा यह अपने अस्तित्व के लिए व्यवहार्य और बड़े पैमाने पर समाज के लिए मूल्यवान बन जाएगा।

डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि PACS राज्यों की एक ऐसी संस्था है जो एक अधिनियम द्वारा समर्थित है। राज्य सरकारों में ऐसे बहुत कम संस्थान हैं जो कानून द्वारा समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि PACS में भारत सरकार के लिए "वन स्टॉप शॉप" बनने की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमें बस यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि ये PACS अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाएँ।

डॉ. भूटानी ने कहा कि हमारे किसानों और ग्रामीणों को मौसम संबंधी सलाह, आपदा संबंधी सलाह, वर्षा पूर्वानुमान, कीट हमले संबंधी सलाह की आवश्यकता है और ऐसी नई तकनीकें उपलब्ध हैं, जिन्हें हमारे ग्रामीण भारत को जागरूक और मजबूत बनाने के लिए सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि PACS को समावेशी, जीवंत और निर्बाध, कुशलतापूर्वक और पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए उभरती हुई तकनीकों की पहचान करना और उन्हें सिस्टम में एकीकृत करना मंत्रालय का काम है।

डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने इस अवसर पर "एक पेड़ मां के नाम" के तहत एक पौधा भी लगाया और भाग लेने वाले सहकारी सदस्यों द्वारा लगाए गए स्टालों का दौरा किया।

कार्यक्रम में उपस्थित PACS सदस्यों ने अपनी चिंताओं को भी व्यक्त किया गया। तीन तकनीकी सत्रों के अलावा, जिसमें क्षेत्रीय आयुक्तों, स्टार्ट अप्स, संबंधित मंत्रालयों और शिक्षाविदों के सदस्यों ने भाग लिया, RCS के अलावा जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और मिजोरम के सचिवों द्वारा भी अनुभव साझा किए गए। कार्यशाला में भाग लेने वाले PACS को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ आज के कार्यक्रम का समापन हुआ।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' का भूमि पूजन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने त्रिभुवन दास पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है

इस यूनिवर्सिटी से सहकारिता में भाई-भतीजावाद खत्म होगा, पारदर्शिता आएगी और सहकारी यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण लेने वालों को रोजगार मिलेगा

इस यूनिवर्सिटी में युवाओं को तकनीकी विशेषज्ञता, अकाउंटेंसी, वैज्ञानिक अप्रोच और मार्केटिंग के साथ-साथ सहकारिता के संस्कार भी सीखने को मिलेंगे

सहकारिता आंदोलन में शिक्षा, प्रशिक्षण और नवाचार के मेगा वैक्यूम को भरने का काम यह यूनिवर्सिटी करेगी, जिसके कारण भारत पूरे विश्व में सहकारिता का गढ़ बनेगा

एक सहकारी नेता हर सदस्य की भलाई के लिए जब काम करता है, तो राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में कितना बड़ा योगदान देता है, इसके आदर्श उदाहरण त्रिभुवन दास जी थे

पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुसंधान और सहकारी संघवाद की भावना के विकास के लिए स्थापित होने जा रही यूनिवर्सिटी के लिए सबसे उचित नाम 'त्रिभुवनदास' है

त्रिभुवन दास जी के ही विजन के कारण दुनियाभर की निजी डेयरियों के सामने आज हमारे देश की कोऑपरेटिव डेयरी सीना तानकर खड़ी है

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने आह्वान करते हुए कहा कि देशभर के सहकारी प्रशिक्षण विशेषज्ञ इस यूनिवर्सिटी से जुड़ें और अपना योगदान दें

नई दिल्ली | केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री मुरलीधर मोहोळ, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने त्रिभुवन दास पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि चार साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के करोड़ों गरीबों और ग्रामीणों के जीवन में आशा का संचार करने और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद से पिछले 4 साल में सहकारिता मंत्रालय ने भारत में सहकारिता क्षेत्र के विकास, संवर्धन और समविकास के लिए 60 नई पहल की हैं। श्री शाह ने कहा कि ये सभी पहल सहकारिता आंदोलन को चिरंजीव, पारदर्शी, लोकतांत्रिक बनाने, विकसित करने, सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन में मातृशक्ति और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए की गई।

श्री अमित शाह ने कहा कि 125 एकड़ में 500 करोड़ रूपए की लागत से देश के पहले त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास सहकारिता क्षेत्र को मज़बूत करने में रह गई सभी कमियों को पूरा करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देशभर में सहकारिता आंदोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक युगांतरकारी कदम है। आज देशभर में 40 लाख कर्मी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हैं, 80 लाख बोर्ड्स के सदस्य हैं और 30 करोड़ लोग, यानी देश का हर चौथा व्यक्ति, सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिता के कर्मचारियों और सहकारी समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए पहले कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहले कोऑपरेटिव में भर्ती के बाद कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी बनने के बाद जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, उसी को नौकरी मिलेगी। श्री शाह ने कहा कि इसके कारण सहकारिता में भाई-भतीजावाद खत्म हो जाएगा, पारदर्शिता आएगी और जो सहकारी यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित होकर निकलेगा, उसी को सहकारी क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में युवा तकनीकी विशेषज्ञता, अकाउंटेंसी, वैज्ञानिक अप्रोच और मार्केटिंग के सारे गुण तो सीखेंगे ही, साथ ही उन्हें सहकारिता के संस्कार भी सीखने को मिलेंगे कि सहकारिता आंदोलन देश के दलित, महिलाओं और आदिवासियों के लिए है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान इस सहकारी यूनिवर्सिटी से हो जाएगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में 2 लाख नए प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) बनाने का निर्णय लिया है जिनमें से 60 हज़ार नए पैक्स इस वर्ष के अंत तक बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 लाख पैक्स में ही 17 लाख कर्मचारी होंगे। इसी प्रकार, कई ज़िला डेयरी बन रही हैं और इन सबके लिए ट्रेंड मैनपावर की ज़रूरत भी त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय पूरा करेगा। श्री शाह ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी सहकारिता में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण और देश के कोऑपरेटिव के विकास की 5 साल, 10 साल और 25 साल की रणनीति बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है। यह यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी तैयार नहीं करेगी बल्कि यहां से त्रिभुवन दास जी जैसे समर्पित सहकारी नेता भी निकलेंगे जो भविष्य में सहकारिता क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। श्री शाह ने कहा कि CBSE ने 9 से 12 कक्षा के पाठ्यक्रम में सहकारिता विषय को जोड़ा है। गुजरात सरकार को भी अपने पाठ्यक्रम में सहकारिता विषय को जोड़ना चाहिए जिससे आम लोग सहकारिता के बारे में जान सकें।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन दास किशिभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। इस कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की नींव पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुसंधान और सहकारी संघवाद की भावना के विकास के लिए डाली गई है, उसके नाम के लिए त्रिभुवनदास पटेल जी से उचित व्यक्ति कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि त्रिभुवन दास जी ने सरदार पटेल के मार्गदर्शन में इसी भूमि पर एक नए विचार का बीज बोने का काम किया था। त्रिभुवन दास जी ने दूध इकट्ठा करने की एक छोटी सी मंडली बनाई और उसके माध्यम से किसानों को सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। श्री शाह ने कहा कि 1946 में खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना हुई और आज त्रिभुवन दास द्वारा बोया गया वह बीज एक विशाल वट वृक्ष बनकर खड़ा है, जिसमें 36 लाख बहनें 80 हजार करोड़ रुपए का कारोबार करती हैं और किसी की 100 रुपए से अधिक पूंजी नहीं लगी है। श्री शाह ने कहा कि Polson की शोषणकारी नीति के सामने सहकारी संगठन की शक्ति को खड़ा करने का काम त्रिभुवन दास जी ने ही किया था। उन्होंने कहा कि आज अमूल विश्व में खाने-पीने की चीज़ों का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरा है। त्रिभुवन दास जी के ही विजन के कारण दुनियाभर की निजी डेयरियों के सामने आज हमारे देश की कोऑपरेटिव डेयरी सीना तानकर खड़ी है। एक सहकारी नेता सहकारिता के हर सदस्य की भलाई के लिए जब काम करता है, तो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया में कितना बड़ा योगदान दे सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण त्रिभुवन दास जी ने प्रस्तुत किया था।

श्री अमित शाह ने कहा कि 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' हमारे देश के मूल विचार और संस्कृति की नींव हैं और उसी से सहकारिता की भावना पैदा हुई है। यह संस्कृति आर्थिक कल्याण के साथ-साथ मानव कल्याण, पशु कल्याण और पर्यावरण को समृद्ध करने के साथ साथ अब गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ सदस्यों वाले सहकारी आंदोलन में शिक्षा, प्रशिक्षण और नवाचार के वैक्यूम को भरने का काम यह सहकारी यूनिवर्सिटी करेगी। यह यूनिवर्सिटी नीतियों का निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देगी, अनुसंधान की नींव डालेगी, प्रशिक्षण देगी और देशभर के सहकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण का एकसमान कोर्स तैयार कर सहकारिता को एकसाथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। यह यूनिवर्सिटी प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी और यहीं से सहकारिता की नीति बनेगी, जो सबका मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि 2 लाख नए और 85 हजार पुराने पैक्स के माध्यम से सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम भी यह विश्वविद्यालय करेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जिस मेगा वैक्यूम ने हमारे सहकारिता आंदोलन को सिकोड़कर रख दिया था उसे भरने का काम यह यूनिवर्सिटी करेगी जिसके कारण अब सहकारिता आंदोलन फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा और भारत पूरे विश्व में सहकारिता का गढ़ बनेगा। त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी, यहां बनाई हुई नीतियां और अभ्यासक्रम, सहकारिता के आर्थिक मॉडल को एक जनआंदोलन में परिवर्तित करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी बड़ी सहकारी संस्थाओं के लिए योग्य कर्मचारी प्रदान करने का काम यह यूनिवर्सिटी करेगी। श्री शाह ने कहा कि हम कोऑपरेटिव टैक्सी लाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनाना चाहते हैं तो हमें हर क्षेत्र के विशेष ज्ञान वाले अधिकारी, कर्मचारी और सहकारी नेता भी चाहिए। उन्होंने पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र का आह्वान करते हुए कहा कि देशभर के सहकारिता प्रशिक्षण विशेषज्ञ इस यूनिवर्सिटी से जुड़ें और अपना योगदान दें।

श्री शाह की अध्यक्षता में हुई सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक

मंत्री श्री सारंग ने साझा किए प्रदेश के नवाचार और दिये सुझाव

भोपाल : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की 'मंथन बैठक' हुई। बैठक में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्यप्रदेश की सहकारिता से जुड़ी उपलब्धियों, नवाचारों और सहकारिता के क्षेत्र में भविष्य की दिशा पर केंद्र सरकार को सुझाव दिये। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर एवं श्री मुरलीधर मोहोल, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश में बहुद्देशीय पैक्स के सफल क्रियान्वयन की जानकारी

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि मध्यप्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को बहुद्देशीय इकाइयों के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार को उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस पहल के अंतर्गत प्रदेश में प्रत्येक पैक्स को उनके संचालन के लिये वार्षिक 3 लाख 24 हजार रुपये की वित्तीय सहायता तथा जनजातीय क्षेत्रों में 3 लाख 48 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि नई पैक्स की स्थापना और उनके आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता आधारित सेवाओं का विस्तार और सशक्तीकरण संभव हो सके।

भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार के लिये केंद्रीय एजेंसी का गठन आवश्यक

मंत्री श्री सारंग ने सहकारिता संस्थाओं में पदों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और एकरूप बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र में आईबीपीएस जैसी संस्था के माध्यम से भर्ती होती है, उसी प्रकार पंचायत एवं ग्रामीण स्तर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक केंद्रीयकृत भर्ती बोर्ड/एजेंसी का गठन किया जाए, जिससे सहकारी आंदोलन को दक्ष मानव संसाधन मिल सके।

सहकारी बैंकों के माध्यम से फंड डिपॉजिट का दिया सुझाव

मंत्री श्री सारंग ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहकारिता संबंधी योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली निधि को जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से डिपॉजिट किया जाए, जिससे इन बैंकों की क्रेडिट क्षमता और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ सके, इससे सहकारी बैंकिंग तंत्र और अधिक मजबूत होगा।

बीज क्षेत्र में नवाचार : 'चीता ब्रांड'

मध्यप्रदेश में बीज संघ को सशक्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 'चीता ब्रांड' बीजों की शुरुआत की गई है, जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीज लगभग आधी कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

कमजोर सहकारी बैंकों के लिए तकनीकी सहयोग की आवश्यकता

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को ध्यान में रखते हुए सहकारी संस्थाओं की पंजीयन से लेकर परिसमापन तक की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है, जिससे संस्थाओं की कार्य-क्षमता में सुधार आया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वित्तीय रूप से कमजोर सहकारी बैंकों को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से तकनीकी और विशेषज्ञ सहयोग दिया जाए, ताकि वे भी मुख्यधारा से जुड़ सकें और ग्रामीण वित्तीय ढांचे को मजबूती दे सकें।

"हर गांव में कोऑपरेटिव" लक्ष्य को लेकर अमित शाह ने सहकारिता मंत्रियों संग की 'मंथन बैठक'

नई दिल्ली | केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष - 2025 के उपलक्ष्य में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ "मंथन बैठक" की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। "मंथन बैठक" का सफलतापूर्वक आयोजन सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बैठक में देशभर के सहकारिता मंत्रियों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सहकारिता विभागों के सचिवों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंथन बैठक का उद्देश्य भारत में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा, उपलब्धियों का आंकलन और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करना है।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना देश में बहुत पुराने सहकारिता के संस्कार को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ नए परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर की है। उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक परिवर्तन और नया परिदृश्य नरेन्द्र मोदी सरकार आने के बाद आया है। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 60-70 करोड़ लोग ऐसे थे, जिनके पास कई पीढ़ियों तक जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थीं। उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 तक के 10 साल के कालखंड में ही मोदी सरकार ने इन करोड़ों लोगों का जीवनस्वप्न पूरा कर दिया और इन्हें घर, शौचालय, पीने का पानी, अनाज, स्वास्थ्य, गैस सिलिंडर आदि सुविधाएं प्रदान कर दीं। श्री शाह ने कहा कि ये करोड़ों लोग अब अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए उद्यम करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पूंजी नहीं है और इन करोड़ों लोगों की छोटी-छोटी पूंजी से बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता सहकारिता है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए दो चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं – जीडीपी और जीएसडीपी का विकास और 140 करोड़ के लिए रोजगार का सृजन करना। उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति के लिए रोजगार के सृजन के लिए सहकारिता के सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है और इसीलिए 4 साल पहले दूरदर्शिता के साथ सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। श्री शाह ने कहा कि हमें संवेदनशीलता के साथ देश के करोड़ों छोटे किसानों और ग्रामीणों के कल्याण के लिए सहकारिता को पुनर्जीवित करना ही होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि इस चिंतन और मंथन से तभी भला हो सकता है जब देश के 140 करोड़ लोग रोज़गार प्राप्त कर परिश्रम के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और इसे सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने 60 से अधिक पहल किये हैं। उन्होंने कहा कि इन पहलों में से एक महत्वपूर्ण पहल है राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण, जिसकी मदद से हम वैक्यूम ढूंढ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस इसीलिए बनाया गया है कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तहसील स्तर की सहकारी संस्थाएं मिलकर ये देख सकें कि किस राज्य के किस गांव में एक भी सहकारी संस्था नहीं है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में देश में एक भी गांव ऐसा न रहे, जहां एक भी कोऑपरेटिव न हो और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग करना चाहिए।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत में सहकारिता आंदोलन के छिन्न-भिन्न होने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। हमने समय के साथ कानून नहीं बदले, जो अब मोदी सरकार ने बदल दिए हैं। हमने सहकारिता में अन्य गतिविधियों को नहीं जोड़ा या समय के साथ बदला नहीं था। उन्होंने कहा कि पहले सहकारिता में सारी भर्तियां भाई-भतीजावाद से होती थीं और इसीलिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का विचार किया गया। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने आग्रह किया कि हर राज्य की कम से कम एक सहकारी प्रशिक्षण संस्था, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े और राज्य के कोऑपरेटिव सेक्टर की ट्रेनिंग की हॉलिस्टिक व्यवस्था त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही हो। श्री शाह ने कहा कि कुछ ही समय में राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा भी होगी जो 2025 से 2045 तक, यानी लगभग आजादी की शताब्दी तक अमल में रहेगी। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय सहकारिता नीति के तत्वाधान में ही हर राज्य की सहकारिता नीति वहां की सहकारिता की स्थिति के अनुरूप बने और इसके लक्ष्य भी निर्धारित हों। उन्होंने कहा कि तभी आज़ादी की शताब्दी तक हम एक आदर्श कोऑपरेटिव स्टेट बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र में अनुशासन, नवाचार और पारदर्शिता लाने का काम मॉडल एक्ट से होगा। उन्होंने कहा कि 2 लाख बहु-उद्देशीय पैक्स के निर्माण के निर्णय के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लक्ष्य को फरवरी माह में ही समाप्त कर दिया जाए, तभी हम 2 लाख पैक्स के लक्ष्य तक समय से पहुंच सकेंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसायटी पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अब कोऑपरेटिव बैंक को हमने बैंकिंग एक्ट के तहत ले आए हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी लचीली अप्रोच अपनाते हुए हमारी कई समस्याएं दूर की हैं।

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

"मोदी युग में सहकारिता को मिला नया जीवन, 31 करोड़ लोगों से जुड़ी 8.4 लाख समितियाँ सक्रिय"

- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया
- सहकारिता हमारे समाज का संस्कार है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसे विधायी रूप देते हुए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया
- सहकारिता मंत्रालय बनाकर मोदी जी ने लगभग 31 करोड़ लोगों से जुड़ी 8.4 लाख से अधिक सहकारी समितियों में नए प्राण फूंकने का काम किया
- विगत 4 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने पांच P - People, PACS, Platform, Policy और Prosperity – पर आधारित 60 से अधिक पहलें की हैं
- सहकारिता मंत्रालय की सभी पहलों की नींव में एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज को समृद्ध व संपन्न बनाने की धारणा है
- 2 लाख नए पैक्स, सहकारिता यूनिवर्सिटी, सहकारी डेटाबेस जैसी पहलें देश के सहकारिता आंदोलन को बहुत मजबूत करेंगी
- इस सहकारिता वर्ष में हमें पारदर्शिता, तकनीक की स्वीकार्यता और सहकारी सदस्य को सहकारी संस्थाओं के केन्द्र में लाने के कार्य को मजबूती के साथ जमीन पर उतारना है
- दूध से लेकर बैंकिंग, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग व कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक, आज सहकारी समितियाँ पूरी सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं
- आज शुरू हुई कच्छ जिला नमक सहकारी समिति आने वाले दिनों में नमक उत्पादन करने वाले हर मजदूर के लिए एक सशक्त सहकारी आंदोलन बनेगी
- 'सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन' दुग्ध की निष्पक्ष खरीद, मूल्य अंतर की भरपाई और डेयरी क्षेत्र में सर्कुलर इकॉनमी का पूरा चक्र स्थापित करेगी
- गृह मंत्री ने देशभक्त और दूरदर्शी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कश्मीर के लिए स्वयं का बलिदान देने वाले डॉ. मुखर्जी जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाया
- NDDB और अमूल, रेडी टू यूज कल्चर के उत्पादन से भारत को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं
- अमूल की चॉकलेट व चीज संबंधी रु. 365 करोड़ की दो परियोजनाओं के शुभारंभ से भारत, डेयरी प्रॉडक्ट्स में और अधिक आत्मनिर्भर होगा

नई दिल्ली | केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने एवं सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। श्री अमित शाह ने खेड़ा स्थित अमूल चीज प्लांट और मोगर स्थित अत्याधुनिक चॉकलेट प्लांट के विस्तार का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने आज आणंद में NCDFI के नए कार्यालय भवन, NDDB कार्यालय परिसर में मणिबेन पटेल भवन का उद्घाटन और रेडी टू यूज कल्चर संयंत्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल, केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और श्री मुरलीधर मोहोल, केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री श्री एस पी सिंह बघेल और केन्द्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GC-MMF) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन पश्चिम बंगाल में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद जी ने आज़ादी के पहले से ही देश की अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को संगठित किया।

उन्होंने कहा कि अगर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर कभी भारत का अभिन्न हिस्सा न होता। श्री शाह ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद ने ही देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे का नारा दिया और कश्मीर के लिए बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल भी डॉ. श्यामा प्रसाद जी के कारण ही भारत का हिस्सा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमारे देश में सहकारिता हमारे समाज के संस्कार के रूप में वैदिक काल से चली आ रही है और इसी संस्कार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विधायी रूप देते हुए आज के ही दिन देश में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि लगभग 31 करोड़ लोगों के साथ जुड़ी 8 लाख 40 हज़ार से अधिक समितियों के अंदर नए प्राण फूंकने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने कहा कि दूध से लेकर बैंकिंग, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थापना के 4 साल में सहकारिता मंत्रालय द्वारा 60 से अधिक पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी पहल पांच P - People, PACS, Platform, Policy और Prosperity – पर आधारित हैं। पहला, People, इन सारी पहल की पूरी लाभार्थी देश की जनता है। दूसरा, PACS, हम प्राथमिक सहकारी मंडलियों को मज़बूत कर रहे हैं। तीसरा, Platform, हमने हर प्रकार की सहकारिता गतिविधि के लिए डिजिटल और नेशनल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम किया है। चौथा, Policy, नमक उत्पादन का मुनाफा भी अब नमक बनाने वालों को मिलेगा। पांचवा, Prosperity। उन्होंने कहा कि Prosperity एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की और संपन्नता कुछ सेठों की नहीं बल्कि गरीबों, मज़दूरों और किसानों की हो और इसी कॉन्सेप्ट के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये 60 पहलें की हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि संगठित बाज़ार, इनपुट सेवाएं, दूध की निष्पक्ष खरीद, मूल्यांतर का भाव और डेयरी सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी का एक चक्र पूरा करने का काम सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन करेगा। उन्होंने कहा कि अमूल की ही तर्ज पर यह देश के किसानों का भला करेगा। उन्होंने कहा कि कच्छ जिला नमक सहकारी समिति के रूप में एक मॉडल समिति कीशुरुआत की गई है जो आने वाले दिनों में नमक उत्पादन करने वाले हर मजदूर के लिए अमूल की तरह सशक्त कोऑपरेटिव आंदोलन बनेगा। श्री शाह ने कहा कि आज अमूल FMCG ब्रांड न सिर्फ भारत बल्कि विश्व का सबसे मज़बूत ब्रांड है और सहकारिता के इस संस्कार का विस्तार करने का संकल्प हमने सहकारिता वर्ष में लिया है। उन्होंने कहा कि कल ही त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है और आज लगभग 10 बहुत बड़ी परियोजनाओं की शुरूआत भी हुई है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख नए पैक्स, सहकारिता यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, अनाज की ब्रिकी और उत्पादन से जुड़ी तीन राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव्स और तीन राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव्स जो डेयरी क्षेत्र के लिए बनती हैं, ये सभी आठों पहल एकसाथ हमारे देश के सहकारिता आंदोलन को बहुत मज़बूत करेंगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमें पारदर्शिता, तकनीक को स्वीकारने और केन्द्र में सहकारिता सदस्य लाने के कार्य को बहुत मज़बूती के साथ इस सहकारिता वर्ष में ज़मीन पर उतारना है। उन्होंने कहा कि जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तब तक सहकारिता लंबी नहीं चल सकती और पारदर्शिता का अभाव ही सहकारिता की भावना को नुकसान पहुंचाता है।

श्री शाह ने कहा कि जहां भी तकनीक को स्वीकारा नहीं गया वहां सहकारिता प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकी और जिस सहकारी संस्था में सदस्य के हित को सर्वोपरि नहीं माना गया वो सहकारी संस्था भी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि इन तीनों चीज़ों को सहकारिता वर्ष में सभी सहकारी नेता अपने कार्यक्षेत्र में ज़मीन पर उतारें और इन्हें अपने काम करने का संस्कार बनाएं और इस भावना को देश के हर ज़िले में पहुचाएं।

श्री अमित शाह ने आज त्रिभुवनदास फूड कॉम्प्लेक्स, मोगर में रु. 105 करोड़ की लागत से निर्मित अमूल के चॉकलेट प्लांट के विस्तार व खात्रज में रु. 260 करोड़ की लागत से निर्मित डॉ. वर्गीस कुरियन चीज प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। अमूल के चॉकलेट प्लांट विस्तार से इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 30 टन से बढ़कर 60 टन प्रति दिन हो जाएगी। डॉ. वर्गीस कुरियन चीज प्लांट में इसके साथ ही UHT दूध, Whey-based ड्रिंक्स, मोजरेला चीज, प्रोसेस्ड चीज पैकिंग, स्मार्ट वेयरहाउस आदि का उद्घाटन भी हुआ है।

साथ ही, केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने NDDB के रु. 45 करोड़ की लागत से निर्मित रेडी-टू-यूज़ कल्चर (RUC), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ (NCDFI) के रु. 32 करोड़ की लागत से नवनिर्मित मुख्यालय भवन का लोकार्पण व NDDB मुख्यालय, आणंद के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया।

"सहकार से समृद्धि' को साकार करता भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड - NCOL की नई उड़ान"

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने विश्व व्यापार केंद्र, नई दिल्ली में भारत ऑर्गेनिक्स मेला 2025 का उद्घाटन किया

भारत ऑर्गेनिक्स मेला इस बात का उदाहरण है कि कैसे सहकारी मॉडल छोटे किसानों को सशक्त बना सकता है और भारतीय घरों तक सुरक्षित, जैविक भोजन पहुंचा सकता है: श्री कृष्ण पाल

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री के मार्गदर्शन में NCOL 'Whole of Government' दृष्टिकोण अपनाकर 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार कर रहा है

NCOL न केवल प्रीमियम मूल्य प्रदान करेगा बल्कि किसान सहकारी समितियों के साथ लाभ भी साझा करेगा: डॉ. आशीष कुमार भूटानी

19 राज्यों की 7,000 से अधिक सहकारी समितियों के साथ, भारत ऑर्गेनिक्स वैश्विक उपभोक्ताओं के साथ घरेलू जैविक उत्पादों की एक मजबूत, विश्वसनीय और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला बना रहा है

भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड बिगबास्केट, ब्लिंकिट, अमेज़न, स्विगी जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और 'सफल' स्टोर्स जैसे प्रमुख खुदरा दुकानों पर उपलब्ध है, जिससे लाखों भारतीय परिवारों को प्रामाणिक जैविक स्वास्थ्य उत्पाद सुलभ हो रहे हैं

नई दिल्ली | केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) द्वारा सहकारिता मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत ऑर्गेनिक्स मेला 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ आशीष कुमार भूटानी और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा देश भर से आए जैविक किसान समूह मौजूद थे।

इस अवसर पर बोलते हुए, सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा, "भारत ऑर्गेनिक्स मेला इस बात का उदाहरण है कि कैसे सहकारी मॉडल छोटे किसानों को सशक्त बना सकता है और भारतीय घरों तक सुरक्षित, जैविक भोजन पहुँचा सकता है। NCOL जैविक खेती को किसानों के साथ एक राष्ट्रीय जन आंदोलन में बदल रहा है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, NCOL, 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण को अपनाकर, 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण को वास्तविकता में ला रहा है। आइए हम सब मिलकर जैविक खेती को न केवल एक विकल्प बल्कि एक आंदोलन बनाएं - जिससे हमारे पर्यावरण, हमारी मिट्टी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को लाभ हो।"

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "NCOL को भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत ब्रांडिंग, प्रमाणन और बाजार पहुंच के माध्यम से जैविक किसानों को संगठित करने और उनका उत्थान करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में देखा जाता है। यह मेला एक पारदर्शी और किसान-प्रथम जैविक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो जमीनी स्तर के उत्पादकों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ सकता है। अब, जैविक किसान समूहों को विपणन मुद्दों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि NCOL उनकी मदद के लिए यहाँ है। NCOL न केवल प्रीमियम मूल्य प्रदान करेगा, बल्कि किसान सहकारी समितियों के साथ लाभ भी साझा करेगा।"

NCOL के अध्यक्ष श्री मीनेश शाह ने कहा, "19 राज्यों की 7,000 से अधिक सहकारी समितियों के साथ, भारत ऑर्गेनिक्स एक मजबूत, विश्वसनीय और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला बना रहा है जो भारत के जैविक उत्पादकों को घरेलू और वैश्विक उपभोक्ताओं से जोड़ती है। NCOL का लक्ष्य अगले दशक में घरेलू जैविक बाजार में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक बनना है और भारत के लिए किसान-स्वामित्व वाला, पारदर्शी और स्केलेबल जैविक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना जारी रखेगा।"

NCOL के प्रबंध निदेशक श्री विपुल मित्तल ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी हितधारकों को धन्यवाद दिया और कहा, "NCOL सभी हितधारकों-किसानों, सहकारी समितियों, मंत्रालयों और भागीदारों के समर्थन के लिए बहुत आभारी है। आज का मेला उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य और किसानों को मूल्य प्रदान करने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हम यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड एक बड़ी सफलता बने और जैविक किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की सेवा करना जारी रखे।"

मेले का मुख्य आकर्षण भारत ऑर्गेनिक्स के प्रीमियम-क्वालिटी ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर (ACV) का लॉन्च था, जिसे भारत के सबसे बड़े सिरका उत्पादक, उनाती कोऑपरेटिव के सहयोग से विकसित किया गया है। पारंपरिक किण्वन (fermentation) तकनीकों का उपयोग करके हाथ से चुने गए हिमालयी सेबों से तैयार किया गया, ACV अनफ़िल्टर्ड, अनपाश्चुराइज़्ड और प्रोबायोटिक्स से भरपूर है - जो प्रामाणिकता और शुद्धता के साथ स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। उनाती स्थानीय समुदायों की महिलाओं के नेतृत्व वाली टीमों द्वारा संचालित आधुनिक, रसायन-मुक्त किण्वन सुविधाएँ संचालित करती है। NCOL के साथ इसका सहयोग ग्रामीण आजीविका, स्वदेशी स्वास्थ्य परंपराओं और सतत विकास को बढ़ावा देने के साझा मिशन को रेखांकित करता है। Certified by FSSAI, USFDA, USDA Organic, and India Organic द्वारा प्रमाणित, ACV अब भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत बिगबास्केट, ब्लिंकिट, अमेज़न, स्विगी जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और सफल स्टोर्स सहित प्रमुख खुदरा दुकानों पर उपलब्ध होगा, जिससे लाखों भारतीय परिवारों को प्रामाणिक जैविक स्वास्थ्य सुलभ हो जाएगा।

दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम ने जमीनी स्तर के उत्पादक समूहों को बाज़ारों से जोड़ने, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और भारत के बढ़ते सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र की ताकत का जश्न मनाने के लिए एक मंच के रूप में काम किया। यह कार्यक्रम सहकारी मॉडल के माध्यम से भारत के जैविक खेती आंदोलन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम था और इसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के राष्ट्रीय पालन के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था।

NCOL किसान सहकारी समितियों द्वारा संचालित भारत का सबसे बड़ा जैविक पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है। भारत ऑर्गेनिक्स के माध्यम से, NCOL शुद्ध, traceable और नैतिक रूप से प्राप्त जैविक उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, जिससे किसानों के लिए बेहतर मूल्य और घरों के लिए प्रामाणिक गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

इस कार्यक्रम की शुरुआत "एक पेड़ माँ के नाम" नामक वृक्षारोपण अभियान से हुई, जिसमें माताओं और धरती माता के पोषण के सार का जश्न मनाया गया। सभी गणमान्य व्यक्तियों ने डब्ल्यूटीसी के परिसर में पेड़ लगाए।

छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, अरुणाचलप्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, कर्नाटक सहित 15 राज्यों के लगभग 30 किसान समूहों (FPOs/FPCs) ने 60 से अधिक उत्पादों के साथ मेले में भाग लिया। मेले में किसान समूहों द्वारा प्रमाणित जैविक उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले 30 से अधिक स्टॉल शामिल थे। 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के तहत, NCOL ने पहले ही दालें, आटा, प्राकृतिक मिठास, मसाले और बहुत कुछ सहित 25 से अधिक उत्पाद बाजार में पेश किए हैं, और जल्द ही और अधिक जैविक उत्पाद जोड़े जाएंगे।

पारदर्शिता, ईमानदारी और नवाचार से मजबूत होगा सहकारी आंदोलन : मंत्री श्री सारंग

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि पारदर्शिता, ईमानदारी और नवाचार के जरिए सहकारी आंदोलन को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए पूरी सहकारिता की टीम कृत-संकल्पित होकर काम करें। मंत्री श्री सारंग समन्वय भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न पहलुओं पर राज्य स्तरीय सहकारी कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए पैक्स का सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए संभागीय और जिला अधिकारी अधीनस्थ पैक्स का निरीक्षण करें। मुख्यालय के अधिकारियों को भी संभागवार जिम्मेदारी दी जाए, जो उनके अधीनस्थों की समस्या एवं सुझावों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने में पैक्स की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सहकारिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि केडिट मूवमेंट के साथ सहकारिता के विभिन्न आयामों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता का क्लेवर बदल रहा है। सहकारी आंदोलन को पुन: मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है।

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से ही गरीबों के घर में खुशी लायी जा सकती हैं। सहकारिता ही ऐसा नेटवर्क है, जिसके माध्यम से हर घर में रोजगार के नए अवसर पैदा किये जा सकते हैं। सहकारिता की साख के लिए काम करें। लोगों को अच्छे कामों के लिए याद रखा जाता है। ईमानदारी से किया गया कार्य आत्मसंतुष्टि देता है, इसलिए जॉब सेटिस्फेक्शन जरूरी है।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि हाल ही में केन्द्र सरकार को दिए गए प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन मध्यप्रदेश का रहा। इसके लिए उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की नवाचार विंग और सीपीपीपी मॉडल को भूरी-भूरी प्रशंसा मिली है। यही नहीं कंप्यूटराइजेशन की दिशा में भी मध्यप्रदेश देश में नंबर एक पर रहा है, जो सराहनीय है।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कमिटमेंट दक्षता को सिद्ध करता है। सभी टीमवर्क के साथ काम करें। यूनिफार्मलिटी जरूरी है। साफ सुथरा ईमानदारी से किया गया कार्य ही आपकी पहचान बनेगा जिससे आपका नाम होगा। जॉब के लिए ईमानदार रहेंगे, तो सफल होंगे। मंत्री श्री सारंग ने शुरूआत में संभाग और जिलों के आए अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और बिना बताए अनुपस्थित अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।

पैक्स सुदृढ़ हो, यही लक्ष्य : एसीएस श्री वर्णबाल

अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णबाल ने कहा कि हर पैक्स को केडिट के अलावा तीन एक्टीविटी करना जरूरी है। स्थानीय पृष्ठभूमि में अवसरों को तलाश कर बिजनेस बढ़ाना होगा। संभागीय और जिला अधिकारी को एक-एक पैक्स की समयबद्ध तरीके से समीक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि पैक्स सुदृढ़ हो यह लक्ष्य होना चाहिये। बिजनेस सोसायटियों के सदस्यों के खाते हमारे यहां होना चाहिये। साथ ही उनके लिये माइक्रो एटीएम की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक श्री मनोज पुष्प ने कहा कि सहाकारिता के सकारात्मक बदलाव के दौर में अधिकारी अपनी अहम भूमिका को पहचानकर दायित्वों का निर्वहन करें। सहकारिता के मॉडलाइजेशन को धरातल पर क्रियान्वित करें। अधिकारी अपनी लीडरशिप में प्रगति का फॉलोअप लें और पैक्स को बिजनेस यूनिट बनाने में सक्रिय भूमिका निभाए।

अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज कुमार गुप्ता ने स्वागत भाषण में कार्यशाला में हुई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उप सचिव श्री मनोज सिन्हा ने केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत करवाया। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के संयुक्त आयुक्त, उप आयुक्त, जिला सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और समिति प्रबंधकों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश के 50 प्रतिशत ग्रामों को जोड़ेंगे दुग्ध नेटवर्क से : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर किसानों और पशुपालकों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के 50 प्रतिशत गांवों को दुग्ध नेटवर्क में लाने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। नई 381 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कर 9500 दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरी प्रणाली से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को मुख्यमंत्री निवास में पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश के लिए डेयरी विकास योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक संशोधन कर अधिक लाभकारी बनाने के निर्देश दिए थे। अब राज्य में दुग्ध उत्पादन की 72 प्रतिशत संभावित क्षमता को कवर करने और बाजार पहुंच को 15प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने दुग्ध संग्रहण बढ़ाने, दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से देशी नस्ल के पशुओं के लिए मॉडल फार्म विकसित करने, सांची ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ाने, भोपाल दुग्ध संघ के अंतर्गत हीफर रियरिंग सेंटर की स्थापना, दुग्ध उत्पादक किसानों को खरीदे गए दूध की कीमत का समय पर भुगतान, डिजीटाइजेशन वर्क की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

दुग्ध संघों ने बढ़ाई है ढाई से छह रुपए प्रति लीटर राशि

इस अवसर पर बताया गया कि प्रदेश के दुग्ध संघों में न सिर्फ दुग्ध संग्रहण बढ़ रहा है, बल्कि किसानों और दुग्ध उत्पादकों का हित भी सुनिश्चित हो रहा है। दुग्ध संघों में दुग्ध मूल्यों में ढाई रुपए से लेकर छह रुपए तक प्रति लीटर वृद्धि का कार्य किया है। प्रदेश में दो दुग्ध संघों जबलपुर और ग्वालियर में दुग्ध संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जबलपुर और ग्वालियर दुग्ध संघ को दुग्ध उत्पादकों के लंबित भुगतान के लिए दो-दो करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध करवाई गई है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।